[श्री राम लाल राही]

बचत के महत्वपूर्ण कार्य की तरफ लगाया होता तो संचार विभाग से ग्रामीण स्तर तक के आम आदमी को लाभ दृष्टिगोचर होता और सर्वहारी वर्ग के लोग महाजनी कुवृत्ति से मुक्ति पाने के लिये रास्ता पाते। पर प्रौढ़ शिक्षा के ही समान लगता है पोस्ट आफिस खोलने का उद्देश्य गौण होता जा रहा है और स्वार्थ की अभिव्यक्ति होती है। संचार व्यवस्था में लगे अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी शोषण, अन्याय और उत्पीड़न के शिकार हैं। सुविधाओं के नाम पर ड्यूटी करते समय मर जाने पर भी सरकार की तरफ से इन्हें वैधानिक या मानवीय रूप से किसी भी प्रकार की सुविधाओं की व्यवस्था नहीं की गई है और न इन के परिवार के राहत की व्यवस्था। लंबी अवधि तक कार्य करने के बाद भी कोई कर्मचारी न तो रेगुलराइज हो पाता है न स्थायी, न पदोन्नति के अवसर उन के लिये उपलब्ध होते हैं। डाक सुरक्षा के लिये वे भीगते हुए थैला ले कर क्यों न जांय, उन के लिये अन्य कर्मचारियों की तरह छाते तक की व्यवस्था नहीं है। न ही चिकित्सा की कोई सुविधा है, न आवासीय, जब कि समान काम के लिये समान वेतन के सिद्धांत के आधार पर इन्हें भी पूर्णकालिक विभागीय कर्मचारी मान कर समस्त सुविधायें दी जानी चाहिये। मेरी सरकार से मांग है कि अल्प बचत योजना से समस्त ग्रामीण क्षेत्रीय सब पोस्ट आफिस के कर्मियों को युद्ध स्तर पर लगाना चाहिये ताकि साधारण किसानों, श्रमिकों, खेतिहर मजदूरों, ग्रामीण शिल्पकारों, को अल्प बचत के लिये प्रेरणा मिले, बचत कर अपने परिवार के पालन-पोषण व राष्ट्रीय निर्माण में भागीदार बनें, महाजनी संकट से छुटकारा पावें, तथा अतिरिक्त विभागीय कर्मचारियों को विभागीय कर्मचारी घोषित कर उन्हें रेगुलराइज किया जाये, पदोन्नति के अवसर दिये जायं तथा अन्य डाक विभाग कर्मचारियों के समान चिकित्सा स्वास्थ्य, वस्त्रों आदि की सुविधायें दी जायं।

(vi) NEED FOR NATIONALISATION OF M/s MOTOR AND MACHINERY MANUFACTURERS, LTD. CALCUTTA

SHRI KRISHNA CHANDRA HALDER (Durgapur): Sir, Motor and Machinery Manufacturers Limited was taken over by the Central Government on 9-10-1974. Since then the industry has been making remarkable progress in the matter of production of Motors and allied machineries. Motor and Machinery Manufacturers Ltd. Workers Union (CITU) and several Members of Parliament have drawn the attention of the Government of the urgent need for immediate nationalisation or amalagamation of the said unit with BHEL or some such big public sector industry.

Sir, in the month of January last a technical study team of BHEL visited the industry and reported to have submitted a favourable report to the Industry Ministry after its revival scheme has been successfully implemented by this unit due to the sincere cooperation between the workers and the management.

Sir, it is high time the Government should take a decision in the matter either nationalisation or tagging this unit with some big public sector undertaking like BHEL, because of such remarkable progress within a short period.

Under these circumstances, I urge upon the Government to task an early decision with regard to Motor and Machinery Manufacturers Ltd., Calcutta. I also demand that the Minister concerned make a statement in the House in this regard as early as possible stating the Government's decision.

(vii) PLIGHT OF BEEDI WORKERS OF SANTHAL PARGANAS, BIHAR

श्री राम विलास पासवान (हाजीपुर) : बिहार के अत्यन्त पिछड़ा जिला संथाल परगना में करीब चालीस हजार स्त्री-पुरुष और बालक बीड़ी बनाने के काम में लगे हैं। इनमें से 30 हजार देवघर अनुमंडल के हैं। ये सकड़ों गांवों में बिखरे हैं। इन मजदूरों का कोई

मजबूत संगठन न होने के कारण कुछ एकाधिकारी बीड़ी कंपनियां अनेक वर्षों से इन असंगठित मजदूरों का निर्मम शोषण भरपूर कर रखे हैं। बीड़ी मजदूरों को मात्र 3 रुपये से लेकर 4 रुपया तक प्रति हजार की दर से मजदूरी दी जाती है। पत्ता काटने से ले कर बीड़ी बनाने तक एक हजार बीड़ी बनाने में कम से कम 12 घंटे का समय लगता है। बीड़ी मजदूरों को जो भी मजदूरी दी जाती है वह भी नगद भुगतान नहीं दिया जाता है। घटिया किस्म का अनाज दिया जाता है। इस के कारण अनेकों मजदूर हमेशा तरह-तरह की बीमारी से ग्रस्त रहा करते हैं। सैकड़ों बीड़ी मजदूर टी०बी० के शिकार हो कर मौत के दिन गिन रहे हैं। अभी कुछ जगहों पर अधिकारियों को सांट-गांठ कर बीड़ी कंपनियों ने अवैध तालाबंदी करके मजदूरों के खिलाफ तेज हमला शुरु कर दिया है। लगभग 150 कारखानों में तालाबन्दी कर दी गई है, जिससे करीब 15 हजार बीड़ी मजदूर आज बेरोजगार बन भुख मरी के कगार पर हैं।

अतः : सरकार से मांग है कि सरकार बीड़ी उद्योग का सम्पूर्ण राष्ट्रीयकरण कर ले, इससे जहां लाखों मजदूरों का शोषण बन्द होगा, वहीं उत्पादन शुल्क की चोरी भी खत्म हो जायेगी।

SHRI RAM GOPAL REDDY (Nizamabad): I support Shri Paswan, It is a genuine demand.

SHRI RAM VILAS PASWAN: You agree, that it is a genuine demand!

1982-83

DEMANDS FOR GRANTS,

Ministry of External Affairs—Contd.

MR. DEPUTY-SPEAKER: The House will now take up further discussion and voting on the Demands for Grants under the control of the Ministry of External Affairs. Shri Chandrajit Yadav, you were on your legs.

AN HON. MEMBER: When will the Minister reply?

MR. DEPUTY-SPEAKER : Minister will reply at 4 p.m. sharp. we have already announced yesterday.

SHRI RAM VILAS PASWAN (Hajipur): Ten hours have been allotted. But only four hours are left.

MR. DEPUTY-SPEAKER: If your Party Member has not spoken, you will be called to speak. But you have not given your name so far. You leave it to me. You will be called. But you have not given your name.

SHRI RAM VILAS PASWAN: I will give.

SHRI CHANDRAJIT YADAV (Azamgarh): Mr. Deputy-Speaker, Sir, I was saying yesterday that the world situation today has greater impact on the national issues and problems. It is very very difficult today to delink or any country from the international developments and forces which are working on the international scene. It seems that the entire world today is caught in a tragic situation of arms race.

The arms race was never on this level, as it is today. With the help of science and technology, war mongers are trying to play with the life of the people and also to prevent the socio-economic development of the newly-liberated countries. They are going in full swing with the arms race. It is a great tragedy that even in those countries, where the people and Government do not fant any war: those countries which do not believe in arms race and want to mobilise their entire resources for their developmental activities, even they are today being compelled to increase their defence expenditure.

I can understand the attitude of the imperialist countries, who have a certain philosophy, who have unfortunately not